in April 1971. In addition, they have now communicated a requirement of 2 lakh tonnes of rice for East Bengal evacuees.

As regards wheat, the monthly demands received from the State Government during the financial year 1970-71 totalled up to 12.45 lakh tonnes. Their demand for April 1971 was 125 th. tonnes and for each of the months of May and June was 135 th. tonnes.

(b) The increased demand for 6.25 lakh tonnes of rice was communicated by the State Government after their Food Minister's discussion with the Union Agriculture Minister on 17 4.1971. The Government of West Bengal have been told that their revised requirement of rice has been noted and that efforts would be made to meet their full reasonable requirements. Adequate stocks of rice are held by FCI on behalf of the Central Government in their godowns in West Bengal. More rice from other States is being moved to these godowns and releases from stocks in these godowns are made to the State Government every month according to their requirements. The State Government's demands for wheat are already being met in full.

Damage of Foodgrains by Rats

588. SHRI K. S. CHAVDA : Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news appearing in a section of the Press that there are about, 2,400 million rats—an average of over four rats to a person in the country—and they eat away as much as 2 4 million tonnes of foodgrains annually ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to stop the eating away of foodgrains either by reducing rat population or by other adequate measures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes Sir. The news item has been noticed by Government.

(b) The Central Government and the State Governments have taken up rat control work Until the year 1969-70, a scheme to eradicate rats by the use of Rodenticides was being implemented by the Government of India as a Centrally-sponsored scheme through the State Governments, which has been transferred to the State Sector from 1969-70. The various methods of rat control such as trapping, baiting, gassing of burrows are used to control the rat population. The Central Food Department has also intensified the extension work for making improved type of receptacles popular at the farmers' level. Storage of foodgrains is also being modernised by the application of the latest scientific techniques of storage and pest control in order to minimise the damage to foodgrains on account of rats.

चीनी मिलों की और गन्ने की मूल्य की बकाया राशि

589. श्री मोहन स्वरूप
श्री वी० एन० पी० सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अप्रैल मास समाप्त होने पर भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलो की ओर गन्ने के मूल्य के रूप में लाखों रुपए की राशि बकाया है जिसका भुगतान उन्होने रोक लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारण जानने का यत्न किया है; और

(ग) किसानो को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि दिलाने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1970-71 में 30 अप्रैल 1971 तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य के 9257.82 लाख रुपयों में से उस तारीख तक 7282.41 लाख रुपए का भुगतान गन्ना उत्पादको को कर दिया गया था और

मौसम के शुरू में पिछले मौसम (1969-70) के गन्ने के मूल्य के 812.31 लाख रुपए की बकाया राशि में से चालू मौसम (1970-71) के दौरान 30 अप्रैल, 1971 तक 619.59 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। अतः गन्ने के मूल्य का भुगतान पूर्णतया रुका नहीं पड़ा है।

(ख) गन्ने के मूल्य की अधिकतर बकाया राशि मुख्यतः 1969-70 के दौरान रिकार्ड उत्पादन होने से चीनी का स्टाक इकट्ठा हो जाने और पिछले मौसम में अधिक स्टाक के बच जाने के कारण अदा नहीं की गई है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वे चूककर्त्ता चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त से सख्त उपाय करें ताकि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का समय पर भुगतान होता रहे। 15 अप्रैल, 1971 को गन्ने के मूल्य की बकाया स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश में 26 चूककर्त्ता चीनी कारखानों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आठ चीनी कारखानों को रिसीवरशिप के अधीन लाया गया है। कलक्टरों ने 5 चीनी कारखाने की नीलामी की घोषणा की है। एक चीनी मिल के मालिक को गन्ने के मूल्य की राशि का भुगतान रोकने के कारण मालगुजारी हवालात में रखा गया था। तीन चीनी कारखानों ने बकाया राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से करार किया है।

कृषि साधनों के मूल्य में वृद्धि

590. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य में कमी आती जा रही है और किसानों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में अनुपात स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या कृषि के लिये आवश्यक साधन भी बहुत मंहगे हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) गत दशाब्दी (1961-62 से 1970-71) की अवधि में, कृषि जिन्सों का मूल्य प्रायः दुगुना हो गया है, जब कि कृषकों द्वारा क्रय की जाने वाली रुई से निर्मित वस्तुयें, माचिस, तम्बाकू, चाय तथा नमक जैसी बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों में केवल 15 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

1970-71 की अवधि में, कृषि जिन्सों के मूल्यों में 1969-70 की अवधि की तुलना में, 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु कृषकों द्वारा खरीदी जाने वाली कुछ वस्तुओं, जैसे रुई से निर्मित वस्तुयें, चाय तथा नमक के मूल्यों में होने वाली वृद्धि कहीं अधिक अर्थात् 9.2 प्रतिशत से लेकर 29.7 प्रतिशत तक थी। तम्बाकू तथा चर्म उत्पादों (जूतों) के मूल्यों में कुछ ह्रास आया, किन्तु माचिस के मूल्यों में 1970-71 की अवधि में 1969-70 की तुलना में स्थिरता रही। कृषि जिन्सों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ वृद्धि देखने में आई, किन्तु खाद्यान्नों के मूल्य में 1970-71 की अवधि में कुछ कमी आई।

(ख) जी नहीं।

(ग) महत्वपूर्ण कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों बिजली, डीजल, तेल, सीमेंट कीटनाशी औषधियों औजारों तथा उपकरणों, स्नेहक तेलों, लोहे तथा इस्पात निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में 1961-62 से 1970-71 की अवधि में, केवल 21 और 64 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई, जब कि इसी अवधि में कृषि जिन्सों के मूल्यों में शत प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) गत कुछ वर्षों की अवधि में अधिक उत्पादनशील किस्मों को विस्तृत पैमाने पर